प्रवासी राजस्थानियों का मातृभूमि को समृद्ध बनाने में योगदान है : मुख्यमंत्री भजनलाल

मुंबई में ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पानी, ऊर्जा, रोजगार व औद्योगिक विकास पर जोर दिया

मुंबई/जयपुर, 26 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार पानी, ऊर्जा, रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को साकार करने में 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भागीदारी के साथ ही राजस्थानी भाई-बहनों की भी अहम भूमिका होगी।

शर्मा शनिवार को मुंबई में आयोजित ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी देश-विदेश की विभिन्न यात्राओं के दौरान यह देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्मभूमि के विकास में योगदान देने के साथ ही अपनी माटी से जुड़ाव रखते हुए राजस्थान को संवारने और समृद्ध बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि भामाशाहों व प्रवासी भाई-बहनों के सहयोग से राज्य में 45 हजार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुंबई में आयोजित ''कर्मभूमि से मातृभूमि'' कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी राजस्थानी समुदाय से राजस्थान में निवेश करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने एक ऐसी ही पहल जल संचय के क्षेत्र में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में हमें भामाशाहों और प्रवासी भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके तहत राज्य में लगभग 45 हजार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। यह अभियान वर्षा जल की एक-एक बूंद को सहेजकर न केवल जल उपलब्धता बढ़ाएगा बल्कि भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मददगार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्षों से लंबित ईआरसीपी (राम जल सेतु लिंक परियोजना) से जुड़ा समझौता करके हमने इसके कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी समुदाय को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राजस्थान में निवेश से उनका कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ ही प्रदेश की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्थान सरकार हरसंभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों और देश के विभिन्न राज्यों में आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जो कि राज्य सरकार और निवेशकों के मध्य समन्वय का कार्य करेंगे।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जल संचय के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही, घर-घर तक नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, वन राज्य मंत्री मुकेश भाई पटेल तथा जोधपुर विधायक अतुल भंसाली सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी उपस्थित थे।

सांसद हनुमान बेनीवाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे

जयपुर, 26 अप्रेल। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर शनिवार को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ,आरएलपी अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ जालूपुरा स्थित आवास से पैदल शहीद स्मारक पहुंचे और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई।

सांसद ने पीटीआई परीक्षा के छात्रों के दस्तावेज का पुनः सत्यापन कराने सहित कई विषयों पर भी अपनी बात रखी वहीं मीडिया से संवाद करते हुए भजनलाल सरकार पर कई आरोप लगाए और राजस्थान लोक सेवा आयोग में हुए भ्रष्टाचार की बात भी उठाई। दस्तावेजों के साथ आरएएस 2018 भर्ती को लेकर यह बात कही

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, इसके कई प्रमाण है , इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पदमा चौधरी नामक एक अभ्यर्थी जिसकी आरएएस 2018 में 24 वीं रैंक थी और इस अभ्यर्थी ने आरएएस मैंस के 4 पेपर

- **उनकी मुख्य मांग, पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती को रद्द करने की है।**

में अंग्रेजी के प्रश्न संख्या 34 का उत्तर भी नहीं लिखा , उसमें उस मूल्यांकनकर्ता ने पहले तो शून्य नंबर दिए मगर इसके बाद 7 नंबर दे दिए जिससे उसकी रैंक 24 हो गई। यह पूरी सांठ गांठ आरपीएससी के चेयरमैन व कई सदस्यों तथा कोचिंग माफियाओं व सत्ता में बैठे युवाओं के सपनो के सौदागरों के संरक्षण के बिना सम्भव नहीं था, इस अभ्यर्थी के साक्षात्कार में भी 72 मार्क्स दिए गए जो बहुत अधिक है और बिना सांठ - गांठ असंभव है।

बेनीवाल ने कहा कि जयपुर के एक बड़े कोचिंग संस्थान स्प्रिंग बोर्ड के फर्जीवाड़े से एसडीएम बनी इस पदमा चौधरी को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया तथा अपनी कोचिंग के पब्लिकेशन से फर्जीवाड़े से आरएएस बनी पदमा चौधरी के नाम से हिंदी की बुक प्रकाशित करवाई तथा उसमें केवल उसके हिंदी का पेपर ही प्रकाशित किया क्योंकि अंग्रेजी के पेपर में तो खाली पेज में भी 7 मार्क्स दे रखें थे,सांसद बेनीवाल ने सीएम भजनलाल शर्मा व राज्यपाल के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए प्रदेश के युवाओं के हित में राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करके उसका पुनर्गठन करने तथा इस मामले की जांच सीबीआई से करवान तथा फर्जीवाड़े से आरएएस बनी पदमा चौधरी को तत्काल निलम्बित करने व साथ ही आरपीएससी के उस वक्त के तमाम उन सदस्यों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने और उस वक्त के तमाम अभ्यर्थियों की कॉपियों को सार्वजनिक करने की मांग उठाई । शनिवार शाम पहलगाम में हुए आतंकी हमले में दिवंगत हुए नागरिकों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने श्रद्धांजलि अर्पित की,सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। बेनीवाल ने पीएम मोदी से पाक अधिकृत कश्मीर को फिर से भारत के हिस्से में लेने की मांग उठाई, बेनीवाल ने कहा कि मोदी के लिए अब भाषण देने का नहीं बल्कि कुछ करने का समय है।

सुरक्षा विशेषज्ञों की राय में, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनावश्यक वृद्धि से बचा जा सके।

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल राकेश शर्मा ने भी जोर देते हुये कहा है कि जहाँ स्थानीय टकराव तथा भड़काऊ गतिविधियाँ सामान्य बातें है, वहीं दोनों देश आमतौर से रणनैतिक नियंत्रण से काम लेते हैं। उन्होंने कहा, ''ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव युद्ध छिड़ने की स्थिति को प्रभावी तरीके से रोकने का काम करते हैं।''

विश्लेषकों ने पाकिस्तान की खराब होती जा रही आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अलग-थलग पड़ जाना तथा वहां की अंदरूनी अस्थिरता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है तथा कहा है कि ये कारण इस्लामाबाद की लम्बे संघर्ष में पड़ने की संभावनाओं को और भी कम करते हैं। इसके अलावा, वैश्विक ताकतें, जिनमें अमेरिका तथा चीन भी शामिल हैं, से भी अपेक्षा है कि वे स्थानीय तनावों को विरासत बनने से रोकने के लिए अपने कूटनीतिक प्रभावों को काम में लेंगी।

इस बीच, खुफिया एजेंसियों से सचेत किया है कि कुछ समय के लिए आतंकी गतिविधियों में वृद्धि सम्भव है। लेकिन गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात को दोहराया है कि भारतीय सुरक्षा बल किन्हीं भी खतरों को निष्क्रिय करने में पूरी तरह सक्षम हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''सरकार पूरी तरह से सजगता बरत रही है तथा स्थिति की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर सैन्य लामबन्दी की योजनाओं का कोई संकेत नहीं है।''

एक सरकारी बयान में, विदेश मंत्रालय ने उस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता की भारत के संकल्प को दोहराया है, साथ ही यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे से दृढ़तापूर्वक निबटा जायेगा तथा उसका माकूल जवाब दिया जायेगा।

विशेषज्ञों ने आम जनता को सचेत किया है कि वह अप्रमाणित अफवाहों पर धयान नहीं दे तथा सनसनीखेज बातों से कोई मतलब नहीं रखे। अजय साहनी ने धैर्य के महत्व पर जोर दिया है तथा दोनों देशों के बीच सुस्थापित कम्यूनिकेशन चैनलों पर ही विश्वास करने को कहा है। उन्होंने निष्कर्ष के रूप में कहा, ''ऐसी अपेक्षा है कि आगामी दिनों में स्थिति शान्त हो जायेगी, बशर्ते, दोनों पक्ष रणनैतिक धैर्य से काम लेते रहें।'' इस समय, जम्मू-कश्मीर के अधिकांश भागों में हालात सामान्य है, हालांकि संवेदन स्थानों पर सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने पर्यटकों तथा वहां के बाशिन्दों से कहा है कि वे सजग तो रहें, लेकिन आश्वस्त भी रहें कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं।

भारी ''इन्सैन्टिव'' देने के बावजूद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ''ऐसा लगता है कि दोनों सरकारें सावधानी से देख रही हैं और व्यापार को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहतीं,'' उन्होंने कहा। ''कुछ कंपनियाँ बता रही हैं कि वे कुछ वस्तुएँ बिना शुल्क के ला पा रही हैं। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हम उसके इंतजार में हैं।''

फिर भी व्यापक निवेश परिदृश्य एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। वर्ष 2024 में चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश साल-दर-साल 27.1 प्रतिशत गिर गया, जो कि 2008 की वित्तीय मंदी के बाद सबसे तेज गिरावट है। बीजिंग ने इसे स्थिर करने के लिए 20-बिन्दु की कार्य योजना शुरु की, जिसमें दूरसंचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को खोलने की बात शामिल है, लेकिन कारोबारी समुदाय अभी भी संशय में है।

एम चैम चाइना के केवल 33 प्रतिशत सदस्यों ने निवेश माहौल में सुधार की बात कही- जो पिछले वर्ष से महज़ पाँच प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वहीं, खराब होते माहौल की बात करने वाले कंपनियों की संख्या घटकर 28 प्रतिशत रह गई, जो सात प्रतिशत की गिरावट है, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी संख्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 21 प्रतिशत सदस्य कंपनियाँ चीन को शीर्ष निवेश गंतव्य नहीं मानतीं। जो महामारी से पहले की तुलना में दोगुनी संख्या है।

इस समस्या का एक हिस्सा नीतियों को आगे भेजे जाने और कार्यान्वयन के तरीके में है। श्वेतपत्र कहता है, ''हमारे सदस्य कंपनियों के नजरिए से, नीति संबंधी उपायों को विदेशी उद्यमों तक बेहतर ढंग से पहुंचाया जाना चाहिए और सरकार के सभी स्तरों पर समान रुप से लागू किया जाना चाहिए।'' सदस्य कंपनियाँ ''खुले और स्पष्ट संवाद चैनलों'' की मांग कर रही हैं ताकि वे समय पर प्रतिक्रिया दे सकें और अपनी चिंताओं को साझा कर सकें।

व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं के अलावा, अमेरिकी कंपनियों ने संरचनात्मक चुनौतियों को भी उजागर किया, विशेष रुप से डेटा सुरक्षा और तकनीक व वित्त जैसे प्रमुख क्षेत्रों के रणनीतिक अलगाव को लेकर। इसके अलावा विदेशी निवेशित कंपनियों के साथ घरेलू कंपनियों के मुकाबले भेदभाव की भावना भी चिंता का विषय बनी हुई है, भले ही सरकार ने भेदभाव नहीं करने का वादा किया हो।

कुल मिलाकर, श्वेत पत्र एक सतर्क विमुखता की तस्वीर पेश करता है- यह कोई सामूहिक पलायन नहीं है, लेकिन चीन में नया पूँजी, मानव संसाधन या रणनीतिक योजना लगाने में बढ़ती हिचकिचाहट जरुर है। जैसे-जैसे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ जटिल विवादित संबंधों के बीच झूल रही हैं, सामान्य व्यापार की गुंजाइश तेजी से कम होती जा रही है।

अन्य देशों की बात करें, तो अमेरिका की नज़र वियतनाम, मैक्सिको, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, पोलैंड और चेक गणराज्य पर भी है।

वियतनाम ''चीन प्लस वन की'' रणनीति से लगातार लाभ उठा रहा है। उसकी कम मजदूरी लागत, व्यापार समर्थक नीतियाँ और चीन से निकटता के कारण आपूर्ति शृंखला विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्रों के लिए आदर्श स्थान बन गया है।

मैक्सिको अमेरिका के लिए आपूर्ति शृंखला को छोटा करने का एक आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है यूएसएमसीए समझौते, भौगोलिक निकटता और कम लॉजिस्टिक लागतों के चलते।

फिलीपींस, मलेशिया और थाईलैंड आउटसोर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एसैम्बलिंग और सेवाओं के लिए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। ये देश प्रतिस्पर्धी श्रम, बेहतर हो रहे बुनियादी ढांचे और व्यवसाय के अनुकूल नीतियाँ पेश कर रहे हैं।

कुछ अमेरिकी कंपनियाँ, विशेष रुप से हाई-टैक और एयरोस्पेस क्षेत्रों में, पूर्वी यूरोप के देशों- खासकर पोलैंड और चेक गणराज्य -की ओर देख रही हैं, जहाँ कुशल श्रम, यूरोपीय संघ की पहुँच और यूरोप तथा यूरेशिया दोनों बाजारों की सेवा के लिए बेहतर रणनीतिक स्थिति है।

पी.डब्ल्यू.डी. ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की थी। इस प्रावधान के चलते जो अफसर व कर्मचारी 30 जून को रिटायर हुए, उन्हें एक वार्षिक वेतन बढोतरी का लाभ नहीं मिला। इससे उनकी पेंशन व अन्य परिलाभ भी प्रभावित हुए। वहीं राज्य सरकार कर्मचारी को वेतन वृद्धि पूर्व में काम कर चुकी अवधि के आधार पर देती है ना कि अग्रिम अवधि के लिए। ऐसे में यदि कर्मचारी एक साल काम करने के बाद तीस जून को रिटायर होते हैं तो उन्हें भी एक जुलाई से लगने वाली सालाना वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकार है।

याचिका कर्ता के वकील ने कहा, हाईकोर्ट ने प्रार्थी के मामले में राज्य सरकार के संबंधित विभाग को निर्देश दिया था कि वह प्रार्थी को एक वेतन वृद्धि सहित अन्य परिलाभ एक महीने की अवधि में दें। लेकिन अदालती आदेश का पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट अदालती आदेश की पालना सुनिश्चित करे और दोषी अफसरों को दंडित किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

रेल अधिकारियों ने कश्मीर में नए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऊधमपुर श्रीनगर बारामुला रेललिंक के प्रमुख अधिकारियों, जिसमें प्रमुख सुरक्षा आयुक्त पंकज गंगवार और जम्मू डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर भी उनके साथ थे। महाप्रबंधक और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जैसे कि चेनाब और अंजी खड पुलों का निरीक्षण किया, इसके अलावा बनिहाल सुरंग का भी निरीक्षण किया। सूत्रों के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या इन बिंदुओं पर बढ़ा दी गई है। स्टेशनों पर बैगेज स्कैनिंग के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं, साथ ही सुरंगों और पुलों पर भी सुरक्षा कडी की गई है। वर्तमान में ट्रेनें दो मार्गों पर संचालित हो रही हैं: 184 किलोमीटर लंबा संगलदन से बारामुला मार्ग और 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर-कटरा खंड। इसका 111 किलोमीटर लंबा कटरा-बनिहाल खंड सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसमें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि इस खंड में भारत की सबसे लंबी, 12.77 किलोमीटर रेल सुरंग (टी-50), दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल (चेनाब) और अंजी में पहला केबल-स्टे पुल है। इस खंड के 97 किलोमीटर - या 87 प्रतिशत - हिस्से में सुरंगें हैं, जिनमें आठ प्रमुख सुरंगें शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, आर. पी. एफ., जी. आर. पी. और राज्य पुलिस को रेल लाइन के साथ सुरक्षा सूचना साझा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी सुरंगों के सी. सी. टी. वी. फुटेज की निगरानी के लिए समर्पित केंद्रों को सक्रिय किया गया है।

'गिरफ्तारी पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर दो साल से वो काबिज है। इस जमीन का एक व्यक्ति ने फर्जी पट्टा बना लिया। जिसकी सैंथल थाने में शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अदालती आदेश से मामला दर्ज किया गया।

दूसरी ओर सैंथल ग्राम पंचायत ने भी प्रार्थी के पट्टे को वैध बताया। परिवाद में कहा गया कि 19 दिसंबर, 2021 की रात आरोपियों ने पुलिस से मिलीभगत कर उसकी जमीन पर धावा बोल दिया और परिवादी व उसके परिजनों से मारपीट की। वहीं अपने अधीनस्थ कर्मचारी से प्रार्थी के खिलाफ एससी-एसटी व राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करा दिया। इसके अलावा घर की महिलाओं को सूर्योदय के बाद बिना महिला पुलिस की मौजूदगी में गिरफ्तार किया और मेडिकल भी नहीं कराया।

पाक सेना ने रात भर सीमा पर फायरिंग की

नई दिल्ली, 26 अप्रैल। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कठोर निर्णयों से बौखलाए पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार पूरी रात कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की जिसका भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। सेना के सूत्रों ने शनिवार सुबह बताया कि पाकिस्तानी सेना ने 25 और 26 अप्रैल की दरम्यानी रात कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अनेक चौकियों से छोटे हथियारों से फायरिंग की । सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना ने भी इसके जवाब में जोरदार फायरिंग की। फायरिंग के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

मस्जिद पर पोस्टर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

काम करना गलत है। पुलिस से भी हमने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस कमिश्नर ने हमसे दो दिन का समय मांगा है। विधायक लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी विधायक केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते रहे हैं, कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी इमामबाड़े पर, कभी आधार कार्ड के नाम पर, तो कभी मोहल्लों के यूनानी डॉक्टर्स, कभी खाने की होटलों पर पहुंचकर खुद ही गैर कानूनी तरीके से रेड करने लगते हैं।

विधायक रफीक खान ने कहा कि जयपुर हमेशा से अपनायत का शहर रहा है,अफसोस कि आज कुछ लोग इसे बिगाड़ने पर तुले हैं। जामा मस्जिद,जौहरी बाजार की सीढ़ि यों पर चढ़ कर मुस्लिम समाज को उकसाने-चिढ़ाने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो कुत्सित प्रयास विधायक बालमुकुंद आचार्य ने किया है, वह घोर आपत्तिजनक है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पहलगाम के कायराना आतंकी हमले के कारण पूरा देश दुखी है,आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है।मगर कुछ लोग सिर्फ़ हिन्दू-मुसलमान करके देश को अंदर से कमजोर करने में लगे हैं।

'सैन्य अभियानों व आवाजाही की जानकारी का प्रसारण ना करे'

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण न करने की सलाह दी है और कहा है कि अभियानों के मामले में खबर देते समय अभियान पूरा होने और आधिकारिक ब्रीफिंग के आधार पर ही रिपोर्ट दी जाए। मंत्रालय ने सभी मीडिया प्लेटफार्मों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों को इस विषय में वर्तमान सभी नियम कानूनों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है।

- **सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइन्स जारी की**

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को भारत के निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकवादी हमले के बाद मंत्रालय ने शनिवार को जारी इस आशय के परामर्श में कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अत्यंत जिम्मेदारी के साथ काम करें और रक्षा एवं अन्य सुरक्षा से संबंधित अभियानों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें। परामर्श में मीडिया मंचों से यह विशेष ध्यान रखने को कहा गया है कि रक्षा अभियानों या बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का (तत्काल) रियल-टाइम (तत्क्षण) कवरेज, लाइव प्रसारण, या सूत्रों पर आधारित जानकारी का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए।

बयान में कहा गया है कि संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा करने से शत्रुतापूर्ण तत्वों को मदद मिल सकती है और इससे अभियानों की प्रभावशीलता और सुरक्षा बलों के कर्मियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11), और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान, अनियंत्रित कवरेज का राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

लंदन में पाक डिप्लोमैट ने की शर्मनाक हरकत

लंदन/नयी दिल्ली, 26 अप्रैल। पाकिस्तानी राजनयिक की ओर से लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे ब्रिटिश-भारतीयों का गला काटने का इशारा करने का मामला सामने आया है। लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर सैकड़ों ब्रिटिश और भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकवाद हमले के विरोध में प्रदर्शन

- **पाक उच्चायोग पर प्रदर्शन कर रहे ब्रिटिश भारतीयों की तरफ पहले तो उसने विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर वाली तख्ती लहराई, उसके बाद उसने प्रदर्शनकारियों का गला काटने का इशारा किया**

कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पाकिस्तानी राजनयिक ने उच्चायोग की बालकनी से प्रदर्शनकारियों की तरफ गला काटने वाला इशारा किया। ब्रिटिश-भारतीय प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान 'भारत माता की जय' और 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गयी थी। प्रदर्शन के दौरान कर्नल तैमूर राहत नामक पाकिस्तानी राजनयिक ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर वाली एक तख्ती पकड़ रखा थी।

ईडी 28 को महेश जोशी का और रिमांड ले सकती है!

महेश जोशी के पुत्र और उसकी कंपनी से जुड़े लोगों से भी ईडी पूछताछ कर रही है

जयपुर, 26 अप्रेल। जल जीवन मिशन (जेजेएम) में 900 करोड़ के घोटाले के मामले में ईडी की टीम पूर्व मंत्री महेश जोशी से पूछताछ कर रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी 28 अप्रेल तक ईडी की रिमांड में हैं। महेश जोशी ने कोर्ट में तीन डिमांड की थीं। कोर्ट ने तीनों बात मान ली है। उनकी डिमांड थी कि रिमांड के दौरान घर का खाना मिले, समय पर दवा मिले और उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है,उन्हें मिलने दिया जाए।

महेश जोशी से, पूर्व में गिरफ्तार हुए उनके परिचित और जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने बैठा कर पूछताछ की गई। महेश जोशी ने अपने बेटे रोहित जोशी की कंपनी में 50 लाख रुपए डाले थे, उसे लेकर भी ईडी, रोहित और उसकी कंपनी से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। ईडी के अनुसार महेश जोशी के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। जेजेएम घोटाले को लेकर ईडी ने महेश जोशी से कई सवाल पूछे। साथ ही उन कंपनियों के बारे में भी जानकारी ली गई, जिन कंपनियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर दिए गए। जानकारी के अनुसार, टैंडर जिनको मिले वह महेश जोशी के पारिवारिक रिश्तेदार और दोस्त निकले। सूत्रों के अनुसार, कुछ आरोपियों और इंजीनियर्स ने महेश जोशी का नाम सीधे तौर पर लिया है।

- **ईडी के अनुसार उसके पास महेश जोशी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कहते हैं कि कुछ आरोपियों और इंजीनियर्स ने महेश जोशी का सीधे नाम लिया है।**

कानूनी प्रक्रिया के तहत हर दिन महेश जोशी का मेडिकल कराया जाएगा। उनके शुगर, बीपी की जांच सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा की जाएगी। जानकारों का कहना है कि ईडी महेश जोशी का 28 तारीख को रिमांड कुछ और दिन का भी ले सकती है।

गौरतलब है कि जेजेएम घोटाला केंद्र सरकार की, हर घर नल पहुंचाने वाली जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा है। साल 2021 में श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाकर जलदाय विभाग से करोड़ों रुपए के 4 टेंडर हासिल किए थे। श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी कार्य प्रमाण पत्रों से पी.एच.ई.डी. की 68 निविदाओं में भाग लिया था। उनमें से 31 टेंडर में एल-1 के रूप में 859.2 करोड़ के टेंडर हासिल किए थे। वहीं, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी ने 169 निविदाओं में भाग लिया और 73 निविदाओं में एल -1 के रूप में भाग लेकर 120.25 करोड़ के टेंडर हासिल किए थे। घोटाले का खुलासा होने पर एसीबी ने जांच शुरू की। कई भ्रष्ट अधिकारियों को दबोचा। फिर ईडी ने केस दर्ज कर महेश जोशी और उनके सहयोगी संजय बडाया सहित अन्य के ठिकानों पर दबिश दी थी। इसके बाद सीबीआई ने 3 मई 2024 को केस दर्ज किया। ईडी ने अपनी जांच पूरी कर 4 मई को सबूत और दस्तावेज एसीबी को सौंप दिए थे।

भारत को चीन से सबक लेना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिंधू जल प्रणाली की पश्चिमी नदियां, और भारत से गुजरने वाली पूर्वी नदियों में गर्मियों में भारी मात्रा में पानी आता है, जब हिमालय की चोटियों और ग्लेशियरों में तापमान बढ़ता है। हिमालय की बर्फ के पिघलने से लाखों क्यूसेक पानी नदियों में आता है।

हिमालय को भौगोलिक रूप से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताजे पानी का भंडार कहा जाता है, पहले दो भंडार है दोनों ध्रुवीय क्षेत्र। सर्दियों में जो बर्फ जमती है वह गर्मियों में पिघलकर उपमहाद्वीप की नदी में आ जाती है।

सिंधु जल प्रणाली में छह नदियां हैं - पूर्वी नदियां-व्यास, सतलुज और रावी- भारत को दी गई हैं। जबकि पश्चिमी नदियां सिंधू, झेलम और चिनाब- पाकिस्तान के हिस्से में आती हैं। पश्चिमी नदियों को हिमालय की बर्फ पिघलने से भारी मात्रा में पानी प्राप्त होता है। लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में बढ़ते जल प्रवाह को संग्रहित करने के लिए बहुत कम बांध या सरोवर बहुत कम हैं। इस पानी को रोकने की कोशिश विनाशकारी बाढ़ और अन्य खतरों को जन्म दे सकती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जल संबंधी क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता होगी।

सामान्य जानकारी के अनुसार, वर्तमान में इस जल प्रवाह के एक बड़े हिस्से को संग्रहित करने के लिए कोई ठोस आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1960 से अब तक हमने इस दिशा में कोई गंभीर योजना नहीं बनाई है। अगर कोई सुनियोजित योजना बनाई जाती, तो इसका व्यापक प्रभाव होता- केवल पाकिस्तान को नुकसान पहुंताना ही उद्देश्य नहीं होता। यह जल भारत के उत्तरी भागों में कृषि और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए भी वरदान साबित हो सकता था।

अब, जब हमें समझ में आ रहा है कि यह पानी रणनीतिक हथियार बन सकता है, तो ऐसे कार्यक्रम के लिए एकीकृत योजना बनाना समय की मांग है। इसके लिए न केवल तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमता की आवश्यकता होगी, बल्कि भारी पूंजी भी लगानी पड़ेगी। हम पहले ही देख रहे हैं कि चीन किस तरह से हिमालय की ऊपरी जलधाराओं पर बांध बना रहा है ताकि वह वहां के विशाल जल संसाधनों का उपयोग कर सकें। हमें यह जानकर झटका लगता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी को जल प्रवाह को उस जगह से बदलने की योजना पर पहले ही काम कर रहा है जहां से यह पूर्वी हिमालय में घूमती है और भारत में प्रवेश करती है। हमारे विरोधों के बावजूद, चीन इसे अपने मैदानों और खेतों की सिंचाई के लिए मोड़ने की योजना पर काम कर रहा है।

एक बार यह परियोजना पूरी हो गई, तो भारत का उत्तर-पूर्वी हिस्सा और बांग्लादेश के बड़े क्षेत्र रेगिस्तान बन सकते हैं। लेकिन चीन किसी भी देश के विरोध की परवाह नहीं करता।

हमें चीन से प्रेरणा लेकर सिंधू जल प्रणाली पर अपनी योजना बनानी चाहिए, ताकि इस पानी का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। सिंधू जल प्रणाली के लिए संघर्ष अब शुरू हुआ है। अब जब हमने लंबे समय तक प्रवाह को नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता जताई है, तो योजना बनाने और इसके क्रियान्वयन में बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत में ''खून की नदी बहाने'' की धमकी के बजाय, अब समय आ गया है कि भारत वास्तव में इन नदियों का नियंत्रण करे।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908